DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NAME OF NEWSPAPERS– NEW DELHI | SATURDAY | OCTOBER 12, 2024

Ramlilas take over entire city, Dussehra promises to be a grand affair

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The national Capital is in a festive mode as Ramlilas have taken over the city in their entire splendor with Dussehra promising to be a grand affair in Delhi. Devotees are flocking different pandals and Ramlilas across the city with people rejoicing in the festival that celebrates the divine feminine energy and preaches good over evil.

At Madhavdas Park, within the historic Red Fort grounds, the Shri Dharmik Leela Committee is set to host a major event featuring a dramatic reenactment of the legendary Ram-Ravan battle with the presence of both the President and the Prime Minister expected, underscoring the event's national significance. The celebration will also feature the cast of 'Singham Again' participating in the much-anticipated Ravana Dahan at the renowned Luv Kush Ramlila.

The Ramlila will feature prominent Bollywood stars, including Kareena Kapoor, Ajay Devgn, and Rohit Shetty, from the cast of 'Singham Again,' blending traditional drama with contemporary celebrity appeal. BJP President Virendra Sachdeva will also be in attendance, adding to the political significance of the festivities.

Ranjan Dimri

In Dwarka, the Sri Ram Lila Society has created a striking 120-foot effigy of Ravana, inspired by the ancient Ram Mandir temple in Ayodhya. The entrance gates, designed in the South Indian "Gopuram" style, aim to offer attendees a rich cultural experience.

The Luv Kush Ramlila Committee has also constructed a 120-foot-tall Ravana effigy, a project that took two months and involved 18 skilled artisans from Uttar Pradesh and the Delhi-NCR region. Additionally, they have crafted a 100-foot effigy of Meghnaad and a 110-foot effigy of Kumbhkaran, promising a visual spectacle for the audience.

Additionally, the Dussehra celebrations extend beyond these locations. At Ramlila Maidan, known for its grand effigies and deep-rooted history in Dussehra festivities, the Delhi Ramlila Committee will organize various performances and rituals. Lal Qila Maidan in Old Delhi will also continue its tradition of elaborate celebrations with massive effigies.

For those seeking a unique cultural experience, the Shriram Bharatiya Kala Kendra Theater Lawns at Mandi House will host a captivating Ramleela performance followed by the symbolic Ravan Dahan. Meanwhile, the Dwarka Sri Ram Leela Society at PDA Grounds, Sector 10, invites local residents to join in the vibrant festivities.

As Delhi gears up to bid farewell to Ravana, the city comes together in a spirit of unity, celebrating the timeless message of Dussehra: the triumph of good over evil. With cultural performances, distinguished guests, and an air filled with enthusiasm, this year's Dussehra celebrations in Delhi promise to be both memorable and inspiring.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer

NAME OF NEWSPAPERS NEW DELHI | SATURDAY | OCTOBER 12, 2024

Prime Minister will clean the air for Delhi this winter

DEEPAK KUMAR JHA
NEW DELHI

Concerned over the perennial problem of deadly pollution with the onset of winters in Delhi NCR, the Prime Minister's Office (PMO) on Friday set the degree of engagement of stakeholders, including the NCT Government of Delhi, to combat the air pollution particularly augmented due to stubble burning in neighbouring States.

The meeting comes a few days after the Supreme Court came down heavily on the Commission for Air Quality Management (CAQM), for not taking any action on local officers amid a rise in crop burning in north Indian states, which leads to air pollution in Delhi. The SC said not a single committee was formed to tackle the stubble burning issue.

"Every year we see stubble burning. There has been total non-compliance of the CAQM Act. Have committees been constituted? Please show us a single step taken. Which directions have you used under the Act? You are silent spectators. You are doing nothing," the Supreme Court said on September 27, 2024.

Principal Secretary to the Prime Minister, Dr. PK Mishra convened a High Level Task Force meeting for the purpose where he reviewed short term and long measures being undertaken to prevent, and abate, air pollution in Delhi, and simultaneously expressed concern over slow pace of clearance of landfill sites in the national Capital and delays in implementation of waste to energy plans by the civic bodies.

File Photo: The Pioneer

Agriculture stubble burning, a major source of seasonal air pollution in Delhi and neighbouring states was addressed. Although Delhi has a relatively small paddy area, Mishra called for the complete elimination of stubble burning in the city as a model for surrounding regions.

According to a senior official, the meeting focused on assessing the readiness of the Delhi Government and other stakeholders in implementing both immediate and long-term measures to mitigate air pollution in Delhi. The Task Force, comprising senior officials from Central Ministries and the Delhi administration, reviewed current strategies and discussed additional innovative steps to tackle the pollution challenge.

Task Force, consisting of representatives from the Delhi Government, Central Ministries including Secretary MoHUA, Secretary MoEFCC, Delhi Police, the Municipal Corporation of Delhi (MCD), the Delhi Development Authority (DDA), the New Delhi Municipal Council (NDMC), and the Commission for Air Quality Management (CAQM), reaffirmed their collective resolve to abate air pollution in Delhi, especially during the ensuing winter season.

Continued on page 2

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

12 अक्तूबर, 2024 ▶ शनिवार
पंजाब केसरी
DELHI

NAME OF NEWSPAPERS----------

'नाले के सौंदर्यीकरण का काम 'आप' ने नहीं एलजी ने किया'

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें द्वारका में एक ड्रेन एरिया के सौंदर्यीकरण का काम अरविंद केजरीवाल द्वारा कराये जाने का जिक्र किया गया था। डीडीए ने कहा कि यह परियोजना उपराज्यपाल द्वारा पूरी की गयी। आप ने 'एक्स" पर द्वारका के एक नाले के आस-पास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद डीडीए ने बयान जारी किया। वीडियो में पार्टी ने दावा किया कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नाले के आस-पास के क्षेत्र का इस तरह से सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। डीडीए ने भी एक्स पर एक पोस्ट में आप के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का पोस्ट में किया गया दावा 'नाले वाली जगह का अरविंद केजरीवाल द्वारा सौंदर्यीकरण" सरासर गलत है। यह काम उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में डीडीए द्वारा किया गया है। उद्घाटन उपराज्यपाल ने फरवरी 2024 में कर दिया था। प्राधिकरण ने कहा कि यही नहीं, पूरे शहर में डीडीए द्वारा विकास के अनेक कार्य किए जा रहे हैं।

द्वारका में नाले ब्यूटीफाई पर आप की पोस्ट सफेद झूठ : गुप्ता

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी)। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी हर रोज झूठ बोलने के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर आम आदमी पार्टी के हैंडल से पोस्ट की गई एक वीडियो को सफेद झूठ बताया, जिसमें द्वारका में नालों को ढककर ब्यूटीफाई किए गए एक प्रोजेक्ट को दिल्ली सरकार द्वारा किया गया बताते हुए अरविंद केजरीवाल का गुणगान किया गया है। आप के इस वीडियो पर डीडीए ने तुरंत ही प्रतिक्रिया व्यक्त की और जवाब देते हुए कहा कि उक्त विकास कार्य दिल्ली सरकार ने नहीं, बल्कि डीडीए की ओर से किया गया है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। डीडीए की ओर से फरवरी, 2024 में इस प्रोजेक्ट के दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उद्घाटन किए जाने की फोटो भी शेयर की गई है।

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली, शनिवार 12 अक्टूबर, 2024

डीडीए ने कहा- नाले का सौंदर्यीकरण आप ने नहीं, एलजी ने किया

भास्कर न्यूज|नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को आप के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें द्वारका में एक नाला क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का काम पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा कराए जाने का जिक्र किया गया था। डीडीए ने कहा कि इस परियोजना को एलजी ने पूरा किया था। आप ने दावा किया था कि द्वारका में नाले वाली जगह का केजरीवाल द्वारा सौंदर्यीकरण कराया गया है। जवाब में डीडीए ने कहा, आप का दावा 'नाले वाली जगह का केजरीवाल द्वारा सौंदर्यीकरण' सरासर गलत है। ये काम एलजी वीके सक्सेना के नेतृत्व में डीडीए द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन एलजी ने फरवरी 2024 में ही कर दिया था। पूरे शहर में डीडीए विकास के अनेक कार्य कर रहा है जिसका श्रेय आप अथवा किसी और द्वारा लेना उचित नहीं है।

amarujala.com
नई दिल्ली | शनिवार, 12 अक्तूबर 2024

आप और डीडीए आमने-सामने, भाजपा ने साधा निशाना

नई दिल्ली। द्वारका में नालों को ढककर क्षेत्र को सुंदर बनाने के प्रयास को लेकर आप और डीडीए आमने-सामने आ गए हैं। इस मुद्दे पर भाजपा ने आप पर निशाना साधा है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब शुक्रवार की सुबह आप ने द्वारका क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें दावा किया गया कि केजरीवाल के नेतृत्व में

द्वारका में नालों को ढककर क्षेत्र को सुंदर बनाने के मामले में आप ने जारी किया वीडियो

दिल्ली सरकार ने शहर की तस्वीर बदलने का काम किया है।

वीडियो में यह दिखाया गया कि किस तरह से द्वारका में नालों को ढककर वहां के सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। इसके बाद डीडीए ने सोशल मीडिया पर दावों को खारिज किया। डीडीए ने कहा कि द्वारका में चल रहे सभी विकास कार्य उपराज्यपाल के निर्देशानुसार हो रहे हैं और डीडीए की इस परियोजना का उन्होंने फरवरी 2024 में शुभारंभ किया था। डीडीए ने इस कार्यक्रम के फोटो भी सोशल मीडिया पर साझा कर दिए। डीडीए ने कहा कि इन कार्यों से दिल्ली सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। आप गलत तरीके से इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है।

वहीं, डीडीए के सदस्य विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप लगातार केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव करीब आने के कारण आप नेताओं में हताशा दिख रही है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPER SATURDAY, 12 OCTOBER, 2024 | NEW DELHI

Vehicles, dust drive Delhi's AQI decline, says report

Continued from P1

In comparison, there were 159 such days in 2023, 202 in 2022, 168 in 2021, 139 in 2020, 183 in 2019, 206 in 2018, 211 in 2017, and 243 in 2016, highlighting the fluctuations in air quality over the years.

The latest Source Apportionment Study of NCT of Delhi, highlighted in the DPCC's latest report, shows that comprehensive research has identified major contributors to air pollution in Delhi such as vehicular emissions, road dust, construction activities, and biomass burning.

To mitigate these issues, the Delhi government has introduced stringent measures to manage dust from construction and demolition activities, alongside robust controls on vehicular emissions.

The report also emphasises the promotion of electric vehicles (EVs), with authorities targeting the installation of thousands of EV charging stations across the city to facilitate a shift towards cleaner transportation.

REPRESENTATIVE PIC

A notable aspect of this initiative is the deployment of 498 anti-smog guns at large construction sites, following a proportional distribution strategy based on the size of the sites.

According to the Central Air Quality Management (CAQM) Policy, construction sites of up to 5,000-10,000 square meters will see one anti-smog gun, while sites exceeding 20,000 square meters will have four guns installed.

According to the report, key initiatives in the strategy include the enhanced monitoring of air quality at 40 locations across the city and tracking eight critical ambient air quality parameters. This data is essential for understanding pollution trends and implementing targeted interventions, the report read.

Key Points

- A notable aspect of this initiative is the deployment of 498 anti-smog guns at large construction sites
- The report also emphasises the promotion of electric vehicles (EVs), with authorities targeting the installation of thousands of EV charging stations

Meanwhile, the report also highlights that in the fight against biomass burning, inspections of garbage burning sites have increased with 74,832 inspections conducted between October 2023 and September 2024.

A total of 1,321 incidents of open burning were addressed, resulting in fines totalling Rs 6.85 lakhs, the report reads.

Additionally, dust control and management cells have been established by 12 road-owning agencies, including the MCD, NDMC, and DDA, to ensure effective monitoring and compliance.

Additional measures reported include the deployment of Road Sweeping (MRS) machines in August 2024 and the operation of 229 Water Sprinkling Machines (WRS) to suppress road dust.

Authorities are also focusing on the scientific disposal of an average of 141.83 metric tons of road dust daily at designated sites, including Okhla and Ghazipur.

The report also highlights the installation of anti-smog guns on high-rise buildings, with 48 guns installed at government buildings and 50 at private structures. The concerned government authorities have been directed to identify more high-rise buildings for additional installations.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE HINDU -- Sunday, October 13, 2024 DELHI DATED----------

AAP alleges scam in housing scheme; bid to defame, says DDA

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Urban Development Minister Saurabh Bharadwaj on Saturday alleged a scam in the allocation of flats by the Delhi Development Authority (DDA) under its Kalkaji slum rehabilitation project, saying the dwelling units meant for the poor are being given to ineligible people.

The Minister also accused Lieutenant-Governor Vinai Kumar Saxena, who is the DDA Chairperson, of turning a blind eye to the corruption involving "top DDA officials" who he said come under the L-G.

The rehabilitation project, launched under the Centre's flagship Pradhan Mantri Awas Yojana, was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi ahead of the Municipal Corporation of Delhi polls in December 2022.

'System foolproof'

The DDA dismissed the allegations and said it has a "foolproof" system in place to prevent fraudulent allotments.

In a statement, it alleged that its probe into the issue revealed that some people

Bharadwaj alleged that flats under the Kalkaji rehabilitation project were given to ineligible candidates

"associated with a political party" are working at the "behest of a leader" with the sole partisan purpose of "defaming" the urban body and its "popular slum rehabilitation scheme".

The DDA will pursue the matter with the police and take recourse to judicial remedies if required, it added.

'Nothing wrong'

Reacting to the allegations, Delhi BJP president Virendra Sachdeva accused the Urban Development Minister of spreading misinformation against the statutory body.

The BJP leader questioned Mr. Bharadwaj as to why the Aam Aadmi Party government in the Capital did not allocate around 40,000 flats constructed under the Rajiv Awas Yojana during the tenure of the Sheila Dikshit-led Congress government in Narela and Bawana and "left these to ruin".

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

sunday pioneer

NAME OF NEWSPAPER NEW DELHI | SUNDAY | OCTOBER 13, 2024

DDA units meant for slum-dwellers being sold illegaly to ineligible individuals: Bharadwaj

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Senior AAP leader and Cabinet Minister Saurabh Bharadwaj on Saturday alleged a scam in the housing for the poor and said the Delhi Development Authority (DDA) housing units meant for slum dwellers in the city are sold illegally to ineligible individuals. Responding to the AAP's allegations, Delhi BJP president Virendra Sachdeva accused him of spreading misinformation against central agencies. However, Sachdeva refuted the charges and termed the allegations "baseless", an official statement from BJP said. South Delhi MP Ramvir Singh Bidhuri also slammed Bharadwaj for spreading lie, saying he is trying to create a false narrative against the DDA and Raj Niwas.

Bharadwaj alleged in a press conference that these DDA flats are being sold to ineligible individuals, undermining the very

purpose of the initiative aimed at aiding the poor. The slum dwellers, who have been displaced by the Central's government actions, were promised housing that is now falling prey to corruption and this cannot happen without the lieutenant governor's consent, he alleged.

"These flats cannot be sacrificed to corruption without the consent of the Central government's DDA. Such a big scam and corruption were happening right under the nose of the BJP LG and it is not possible that Lieutenant Governor Vinay Saxena was not aware of it," he said. Bharadwaj also accused the BJP of being against the poor.

"The BJP is always troubled by the poor and stands against them. When free electricity and water were given to the poor, the BJP opposed it. Now these flats, which were meant for the poor, are being given in black to other people," he said.

The Delhi Cabinet Minister questioned whether the LG is truly unaware of this corruption, suggesting it is happening with the involvement of top officials from the DDA, which falls under the LG's authority. He took potshots at the BJP for consistently opposing the welfare of slum residents, pointing to the demolition of thousands of slums in the last two years and accusing the party of neglecting the poor.

The Aam Aadmi Party (AAP) leader called for an independent investigation into the matter, suggesting that only a sitting judge from the High Court or Supreme Court could ensure a transparent inquiry.

"If the ACB or CBI investigate, it will likely be covered up, as these agencies work under the LG and the Central government. So, this matter should be investigated by a sitting judge from the High Court or Supreme Court to ensure a transparent inquiry," Bharadwaj said.

Over the past two years, central government agencies like Archaeological Survey of India (ASI), DDA, and Land and Development Office (L&DO) have demolished Delhi's 'jhuggis', rendering lakhs of residents homeless. Those eligible for flats have been evicted, as seen behind DPS Mathura Road, where thousands were displaced by L&DO. In Tughlakabad, the central government's ASI rendered lakhs of people shelterless, and in Mehrauli, thousands more were forced out.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- millenniumpost
NEW DELHI | SUNDAY, 13 OCTOBER, 2024

ALLEGES CORRUPTION; DDA REFUTES CLAIMS

AAP Min says DDA flats being illegally sold, BJP hits back

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi minister Saurabh Bharadwaj on Saturday alleged a scam in the housing for the poor and said that the DDA housing units meant for slum dwellers in the city are sold illegally to ineligible individuals.

Responding to the AAP's allegations, Delhi BJP president Virendra Sachdeva accused him of spreading misinformation against central agencies.

Bharadwaj in a press conference alleged that the DDA flats, under the housing for the poor scheme, are being sold to ineligible individuals, undermining the very purpose of the initiative. The slum dwellers who were displaced by central government actions were promised housing that is now falling prey to corruption, and this cannot happen without the consent of the L-G, Bhardwaj said.

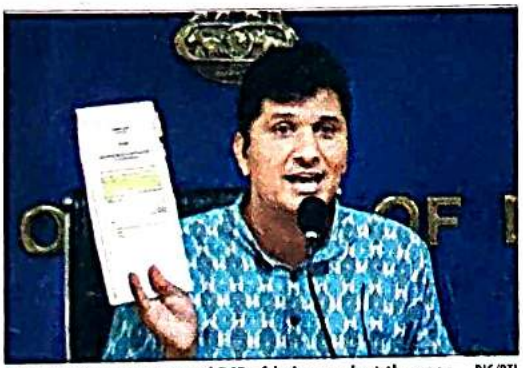

Saurabh Bhardwaj accused BJP of being against the poor PIC/PTI

"These flats cannot be sacrificed to corruption without the consent of the central government's DDA. Such a big scam and corruption were happening right under the nose of the BJP L-G, and it is not possible that L-G Vinay Saxena was not aware of it," he said.

Bharadwaj also accused the saffron party of being against the poor and said: "The BJP is always troubled by the poor and stands against them. When free electricity and water were given, the BJP opposed it. Now these flats, which were meant for the poor, are being given in black to other people."

In response to the AAP's attack, DDA said: "The statements and allegations made by Bharadwaj are false, without any basis and bereft of facts. Not a single flat/dwelling unit in the Kalkaji Slum Rehabilitation project has been allotted to an ineligible benificiary and DDA has fool proof technology enabled systems in place to ensure that no fraudulent allotment/sale is made."

"It is denied that any officials of DDA are involved in any such activity as has been alleged," it added.

Meanwhile, Sachdeva refuted the charges and termed the allegations "baseless", an official statement from the BJP said. Bharadwaj had further called for an independent investigation into the matter, suggesting that only a sitting judge from the high court or Supreme Court could ensure a transparent inquiry. "If the ACB or CBI investigate, it will likely be covered up. So, this matter should be investigated by a sitting judge from the HC or SC to ensure a transparent inquiry," the minister said.

Highlights

- Bharadwaj in a press conference alleged that the DDA flats, under the housing for the poor scheme, are being sold to ineligible individuals, undermining the very purpose of the initiative
- The allegations made by Bharadwaj are patently false, without any basis and bereft of facts, the DDA stated

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। रविवार • 13 अक्टूबर • 2024 | राष्ट्रीय सहारा

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

गरीबों को मिलने वाले आवास में हो रहा भ्रष्टाचार : भारद्वाज

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

- डीडीए के ये फ्लैट अपात्र व्यक्तियों को बेचे जा रहे
- न्यायिक जांच की मांग

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गरीबों को मिलने वाले आवास में घोटाले का आरोप लगा शनिवार को कहा कि शहर में झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों के लिए बने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आवास अवैध रूप से अपात्र व्यक्तियों को बेचे जा रहे हैं। आरोपों पर डीडीए और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नही मिल पाई है।

भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि डीडीए के ये फ्लैट अपात्र व्यक्तियों को बेचे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की कार्रवाई से विस्थापित हुए झुग्गीवासियों को आवास देने का वादा किया गया था जो अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। यह उपराज्यपाल की सहमति के बिना नही हो सकता।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और डीडीए की मिलीभगत के बिना इन फ्लैटों को भ्रष्टाचार की बलि नही चढ़ाया जा सकता। इतना बड़ा घोटाला भाजपा के उपराज्यपाल की नाक के नीचे हो रहा था और यह संभव नही है कि उपराज्यपाल को इसकी जानकारी न हो। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा गरीबों से परेशान रहती है और उनके खिलाफ खड़ी रहती है। जब गरीबों को मुफ्त बिजली और पानी दिया गया तो भाजपा ने इसका विरोध किया। अब ये फ्लैट, जो गरीबों के लिए थे, अन्य लोगों को अवैध रूप से दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर कहा कि केवल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के कोई कार्यरत न्यायाधीश ही पारदर्शी जांच सुनिश्चित कर सकते हैं।

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) या सीबीआई जांच करते है, तो इस पर पर्दा डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये एजेंसियां एलजी और केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए इस मामले की जांच उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए।

केंद्र सरकार और डीडीए की मिलीभगत के बिना इन फ्लैटों को भ्रष्टाचार की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। इतना बड़ा घोटाला भाजपा के उपराज्यपाल की नाक के नीचे हो रहा था और यह संभव नहीं है कि उपराज्यपाल को इसकी जानकारी न हो। ——— सौरभ भारद्वाज, मंत्री, दिल्ली सरकार

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- अमर उजाला 9 नई दिल्ली। रविवार। 13 अक्तूबर 2024 ----ED----

ब्लैक में बेचे जा रहे झुग्गी के बदले मिलने वाले फ्लैट : आप

सौरभ बोले-केंद्र की एजेंसियों ने लाखों लोगों को बेघर किया

अमर उजाला ब्यूरो

प्रेसवार्ता में मंत्री सौरभ भारद्वाज। अमर उजाला

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर झुग्गी के बदले मिलने वाले फ्लैटों को लेकर आरोप लगाया है। आप का आरोप है कि इन फ्लैटों को भ्रष्टाचार के तहत ब्लैक में उन लोगों को बेचा जा रहा है, जो लोग झुग्गी बस्ती में रहने वाले नहीं हैं। मुख्यालय में हुई प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालकाजी में स्थित ऐसे ही फ्लैटों का उद्घाटन किया था, जो कि झुग्गी में रहने वाले व्यक्तियों को झुग्गी के बदले मिलने थे।

भारद्वाज ने कहा कि भाजपा गरीबों के खिलाफ क्यों है। कहा कि दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त की, भाजपा ने इसकी खिलाफत की। जब दिल्ली सरकार ने 20 हजार लीटर पानी गरीबों के लिए मुफ्त किया तो भाजपा ने इसका विरोध किया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पिछले 2 साल में केंद्र सरकार की एजेंसियों जैसे कि डीडीए, रेलवे, एलएनडीओ व एएसआई आदि ने अलग-अलग क्षेत्रों में बसे लिस्टेड क्लस्टर एरिया को उजाड़ा है और लाखों लोगों को बेघर किया है।

भारद्वाज ने कहा कि किसी भी झुग्गी बस्ती में रहने वाले व्यक्ति को झुग्गी के बदले फ्लैट मिलने की एक लंबी प्रक्रिया होती है लेकिन यह फ्लैट उन लोगों को बेचे जा रहे हैं, जिनका न तो किसी झुग्गी बस्ती एरिया में कोई नाम है और न ही वह लोग उस झुग्गी बस्ती के रहने वाले हैं।

एक भी फ्लैट अयोग्य लाभार्थी को आवंटित नहीं किया : डीडीए

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से कालकाजी में झुग्गी के बदले मिलने वाले फ्लैटों को आयोग्य लाभार्थियों को आवंटित करने के आरोपों को तथ्यहीन बताया है। डीडीए ने कहा कि भारद्वाज द्वारा दिए गए बयान और आरोप स्पष्ट रूप से झूठे और बिना किसी आधार के हैं। कालकाजी स्लम पुनर्वास परियोजना में एक भी फ्लैट/आवास इकाई किसी अयोग्य लाभार्थी को आवंटित नहीं किया गया है। डीडीए के पास यह सुनिश्चित करने के लिए फुलप्रूफ प्रौद्योगिकी सक्षम सिस्टम है कि किसी भी अपात्र को आवास आवंटित न हो।

कथित स्टिंग ऑपरेशन में दर्ज एक भी व्यक्ति डीडीए से जुड़ा नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन में ब्लैक मार्किटियर्स के रूप में दिखाए गए व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। डीडीए ने दावा किया कि उनकी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फ्लैटों के व्यक्ति (कालाबाजारी करने वाले) एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। डीडीए को बदनाम करने के एकमात्र पक्षपातपूर्ण उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्र के उस राजनीतिक दल के एक नेता के इशारे पर काम कर रहे हैं। डीडीए पुलिस के साथ मामले को आगे बढ़ाएगा और जरूरत पड़ने पर न्यायिक उपायों का भी सहारा लेगा। पात्र परिवारों को आवंटन जेजे क्लस्टर निवासियों और स्वतंत्र न्यायाधीशों की उपस्थिति में आयोजित कंप्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पात्रता निर्धारण या फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया में डीडीए के कनिष्ठ अभियंता की कोई भागीदारी नहीं है। डीडीए ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वह तथ्यों की जांच किए बिना लगाए गए हैं। पारदर्शिता के उद्देश्य से ड्रॉ के बाद अंतिम रूप दिए गए फ्लैटों के आवंटन की सूची डीडीए वेबसाइट पर भी प्रकाशित की गई है। ब्यूरो

तितलियों का संदेश...जलवायु परिवर्तन के असर को बेअसर कर सकते हैं जैव विविधता पार्क

जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन करने की क्षमता दिल्ली के पार्कों में मौजूद, तापमान बढ़ने के बावजूद तितलियों की प्रजातियों की संख्या में नहीं आई गिरावट

कॉमन जय

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। बड़े मौसमी बदलावों से गुजर रहे दिल्ली सरीखे मेट्रो शहरों के लिए तितलियों ने बड़ा संदेश दिया है। तापमान बढ़ने के बावजूद दिल्ली में डीडीए के सात जैव विविधता पार्कों में तितलियों की प्रजातियों की संख्या में खास गिरावट दर्ज नहीं की गई। देश के सभी पांच तितली परिवारों की 68 प्रजातियों की 8,337 तितलियां डीडीए जैव विविधता पार्कों में मौजूद हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम के बदलते मिजाज के बावजूद जैव विविधता पार्क में तितलियों की विविधता स्थिर है। जबकि तितलियां तापमान के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। पारे में मामूली बढ़ोत्तरी से इनकी संख्या कम हो जाती है। साफ है कि पार्क जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता रखता है। शहरी केंद्रों में विकसित जैव विविधता पार्क जलवायु परिवर्तन के असर को बेअसर कर सकते हैं। दरअसल, बीते पांच सालों से डीडीए के सात जैव विविधता पार्कों में दीर्घकालिक आंकड़े जुटाने के लिए विशेषज्ञ तितलियों की गणना कर रहे हैं। संख्या जानने के साथ सर्वे इसलिए भी अहम था कि तितलियां वायु प्रदूषण, तापमान, बारिश समेत दूसरे पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं।

ब्लैक स्पिफ्ट

कॉमन रोज

सबसे ज्यादा अरावली, कालिंदी में सबके कम तितलियां

जैव विविधता पार्क कार्यक्रम के वरिष्ठ वैज्ञानिकों डॉ. आयशा सुल्ताना और मोहम्मद फैसल की निगरानी में किए गए सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि अरावली जैव विविधता पार्क में तितली की सबसे ज्यादा 58 प्रजातियां देखी गई। कालिंदी जैव विविधता पार्क में इनकी संख्या सबसे कम सिर्फ 18 रही। दूसरी तरफ संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रजातियां प्लेन टाइगर, कॉमन इमोग्रेट येलो ऑरेंज टिप, लेमन पैंसी, कॉमन गल और कॉमन ग्रास येलो तितलियों की मिलीं।

> मौसम के बदलते मिजाज के बावजूद डीडीए जैव विविधता पार्क में तितलियों की विविधता स्थिर रही है। इससे पता चलता है कि जैव विविधता से समृद्ध आवास जलवायु परिवर्तन अनुकूलन करने की क्षमता रखता है। डीडीए जैव विविधता पार्क जलवायु परिवर्तन के प्रभावों सहित पर्यावरणीय मुद्दों के अध्ययन के लिए जीवित प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। डॉ. फैयाज खुदसर, प्रभारी वैज्ञानिक, जैव विविधता पार्क

यह महत्वपूर्ण परागणकर्ता भी हैं। तितलियों की संख्या में कमो-बेशी के सहारे पर्यावरण में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसी कड़ी में यमुना, अरावली, तिलपत वैली, उत्तरी रिज, नीला हौज, तुगलकाबाद और कालिंदी जैव विविधता पार्क में बीते दिनों तितलियों की गिनती की गई। इस दौरान वयस्क तितलियों को धूप सेंकते, प्रजनन करते, अंडे देते हुए रिकॉर्ड किया गया। वहीं, परपोषी पौधों पर लार्वा और अंडे देखे। सर्वेक्षण के नतीजे संतोषजनक रहे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI 13 अक्तूबर, 2024 ▸ रविवार

गरीब झुग्गी वालों को मिलने वाले फ्लैट ब्लैक में बेचे जा रहे: भारद्वाज

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली में गरीब झुग्गी निवासियों को झुग्गी के बदले मिलने वाले पक्के मकान ब्लैक में अन्य लोगों को बेचे जाने का आरोप लगाया है। आप नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों को झुग्गी के बदले पक्का मकान दिया जाता है, ताकि वह लोग और उनके बच्चे एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें और साथ ही साथ दिल्ली में झुग्गियों की संख्या को काम किया जा सके।

हाल ही में जारी हुए एक स्टिंग ऑपरेशन की बात करते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बेहद ही अफसोस जनक और आश्चर्य की बात है कि कालका जी में जिन फ्लैटों का उद्घाटन पीएम ने झुग्गी में रहने वाले

लोगों को आबंटित करने के लिए किया था, उन फ्लैटों को ब्लैक में उन लोगों को बेचा जा रहा है जो लोग झुग्गी-बस्ती में रहने वाले लोग नहीं हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि भाजपा हमेशा गरीबों के खिलाफ क्यों नजर आती है? जब भी कभी गरीबों की भलाई का कोई काम होता है तो भाजपा हमेशा इसकी खिलाफत करती क्यों नजर आती है? अब जो फ्लैट गरीबों के लिए झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए थे, भाजपा शासित केंद्र सरकार की आंखों के सामने वही फ्लैट ब्लैक में अन्य लोगों को बेचे जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले दो साल में हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार की एजेंसियां जैसे कि डीडीए, रेलवे, एलएनडीओ व एएसआई आदि ने अलग-अलग क्षेत्र में बसी लिस्टेड क्लस्टर एरिया को उजाड़ा है और लाखों लोगों को बेघर किया है। उन्होंने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि डीडीए के उच्च अधिकारियों की मिली भगत के बिना यह सब भ्रष्टाचार का खेल किया जा सके। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार के माध्यम से न केवल झुग्गी-बस्ती में रहने वाले लोगों का नुकसान किया जा रहा है।

सौरभ भारद्वाज के आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन व बेबुनियाद: डीडीए

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कालकाजी इलाके में गरीब झुग्गी निवासियों को झुग्गी के बदले मिलने वाले पक्के मकान डीडीए अधिकारियों की मिलीभगत से ब्लैक में अन्य लोगों को बेचे जाने के आरोपों को डीडीए ने पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। इस बारे में डीडीए ने एक बयान जारी कर कहा कि डीडीए का कोई भी अधिकारी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं है। जैसे मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया गया है। डीडीए द्वारा इस बारे में शनिवार को गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन कालकाजी में एक शिकायत दर्ज करायी गई है। अपने बयान में डीडीए ने आगे कहा कि मौजूदा झुग्गी के बदले वैकल्पिक आवास के आवंटन के लिए जेजे क्लस्टर निवासियों की पात्रता डीयूएसआईबी नीति के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तय की जाती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- दैनिक भास्कर | नई दिल्ली, रविवार 13 अगस्त, 2024 | ED----------

आप का दावा • पीएम आवास योजना में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार

झुग्गियों के गरीबों को बेघर कर ब्लैक में बेच रहे फ्लैट: भारद्वाज

एलजी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार, लेकिन वो फिर भी चुप : आप

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई गरीब लोगों को 'जहां झुग्गी वहीं मकान' देने की शुरू की गई योजना में भ्रष्टाचार होने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी वीके सक्सेना पर हमला बोला है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेसवार्ता कर कहा दिल्ली में गरीब झुग्गी निवासियों को झुग्गी के बदले पक्का मकान देने की एक योजना चलाई जाती है, जिसे पीएम आवास योजना कहा जाता है और इस योजना के तहत झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों को झुग्गी के बदले पक्का मकान दिया जाता है। जिससे वह लोग और उनके बच्चे एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें और साथ ही साथ दिल्ली में झुग्गियों की संख्या को काम किया जा सके। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी ने खुद कालकाजी में स्थित ऐसे ही फ्लैटों का उद्घाटन किया था, जो कि झुग्गी में रहने वाले व्यक्तियों को झुग्गी के बदले मिलने थे। इस संबंध में खुलासा हुआ है कि उन फ्लैटों को एक बड़े भ्रष्टाचार के तहत ब्लैक में उन लोगों को बेचा जा रहा है जो लोग झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग ही नहीं हैं।

कैबिनेट मंत्री बोले -भाजपा गरीबों के खिलाफ

भारद्वाज ने कहा आज एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि भाजपा हमेशा गरीबों के खिलाफ क्यों नजर आती है? जब भी कभी गरीबों की भलाई का कोई काम होता है तो यह पार्टी हमेशा उनकी खिलाफत करती क्यों नजर आती है? उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा जब दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त की भाजपा ने इसकी खिलाफत की, जब दिल्ली सरकार ने 20 हजार लीटर पानी गरीबों के लिए मुफ्त किया भाजपा ने इसकी खिलाफत की और जब दिल्ली सरकार ने महिलाओं की बस में यात्रा मुफ्त की भाजपा ने उसकी भी खिलाफत की, और अब जो फ्लैट गरीबों के लिए झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए थे, भाजपा शासित केंद्र सरकार की आंखों के सामने वही फ्लैट ब्लैक में अन्य लोगों को बेचे जा रहे हैं।

केंद्रीय एजेंसियों ने लिस्टेड क्लस्टर एरिया को उजाडा

भारद्वाज ने कहा पिछले 2 साल में केंद्र की एजेंसियां डीडीए, रेलवे, एलएनडीओ आदि ने अलग अलग क्षेत्र में बसी लिस्टेड क्लस्टर एरिया को उजाड़ा है, लाखों लोगों को बेघर किया है। यह वही लिस्टेड क्लस्टर एरिया थे, जिनको झुग्गी के बदले फ्लैट मिलना था। यह सीधे सीधे भ्रष्टाचार का खेल है कि जिन क्लस्टर एरिया को उजाड़ा गया। अब वह लोग दूसरी जगह पर जाकर झुग्गियां बसा रहे हैं, फिर दोबारा उनके नाम पर नए फ्लैट बनाए जाएंगे और फिर ब्लैक किए जाएंगे।

कहां है राजीव आवास योजना के 40 हजार फ्लैट- सचदेवा

आरोप पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा वो केवल केंद्रीय एजेंसियां के विरूद्ध भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने डीडीए के खिलाफ बोला। वो यह बताएं राजीव आवास योजना के नरेला- बवाना में तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार द्वारा बनाए गए 40 हजार फ्लैटों का क्यों हुआ? डयूसिब ने गत 10 साल में कितने गरीबों को घर दिए बताएं? सरकार ने क्यों पीएम आवास योजना यहां लागू नहीं की?

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- पंजाब केसरी सोमवार 14 अक्तूबर, 2024

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सूचना

डीडीए के विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर परामर्शदाता के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डीडीए के विभिन्न विभागों में परामर्शदाता के रूप में 05 नायब तहसीलदार और 03 कानूनगो को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। यह नियुक्ति शुरुआत में 01 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे डीडीए की आवश्यकता और अभ्यर्थी के कार्य निष्पादन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	अनुभव	सेवानिवृत्ति के समय न्यूनतम ग्रेड वेतन
1.	नायब तहसीलदार	05	डीडीए भूमि के राजस्व कार्य में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव	पीबी–2 + जीपी 4200/– रुपये (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6)
2.	कानूनगो	03	डीडीए भूमि के राजस्व कार्य में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव	पीबी–1 + जीपी 2400/– रुपये (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4)

अनिवार्य योग्यता, अधिकतम आयु और अनुभव आदि से संबंधित पूर्ण अधिसूचना के साथ, आवेदन का निर्धारित प्रारूप डीडीए की वेबसाइट https://dda.gov.in/latest-jobs पर उपलब्ध है।

अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में अपने हस्ताक्षरित आवेदन की स्कैन की हुई पीडीएफ/जेपीईजी कॉपी ई–मेल के माध्यम से **ddpb4@dda.org.in** पर **25.10.2024 को शाम 05:00 बजे तक** भेजनी होगी।

डाक या फोन द्वारा किसी अन्य पत्राचार या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसका विवरण डीडीए वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

रिक्तियों की संख्या डीडीए की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

आयुक्त (कार्मिक)

हमें फोलो करें @ddaofficial official_dda official_dda_

"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या 1800110332 डायल करें"

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI SATURDAY, OCTOBER 12, 2024 -DATED----------

Who beautified the drain? Kejriwal, says AAP; DDA fumes

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) on Friday refuted a claim made by AAP regarding the beautification of a drain area in Dwarka by **Arvind Kejriwal**, stating that the project was executed by LG **Saxena**.

Reacting to a video of a beautified drain in Dwarka posted by AAP on X, DDA said the claim was false. In the video, AAP claimed that only Kejriwal, the former Delhi CM and the party's national convener, could undertake such beautification work in the city.

Responding to this, DDA posted on X in Hindi, "The claim made by the Aam Aadmi Party about the beautification of the drain area by Arvind Kejriwal is absolutely false. This work has been done by the DDA under the leadership of LG Vinay Kumar Saxena. It was inaugurated by the LG in February 2024 itself."

The authority added that not just this project, but many development works are being carried out by DDA across the entire city, and no other agency or AAP should take credit for these. It also posted a few photographs of the inspection and inauguration of the Dwarka drain project and other works by the LG. AAP later deleted its post.

The leader of the opposition in the Delhi assembly and DDA member, Vijender Gupta, also termed the AAP post on X a "blatant lie" and said that the party was claiming the development works done by the central govt as its own.

"AAP showed no hesitation while making the video and spreading blatant lies to take credit for the central govt's work. In desperation, AAP is resorting to such falsehoods to mislead the people of Delhi instead of presenting the report card of its own works before the public," he added. Gupta also accused AAP of obstructing the central govt's projects.

No immediate reaction was available from AAP.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- हिन्दुस्तान नई दिल्ली शनिवार, 12 अक्तूबर 2024 ----DATED----

लैंडफिल से कचरा न उठाने पर पीएमओ नाराज

समीक्षा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली की लैंडफिल साइट पर पड़े कचरे को साफ करने की धीमी गति पर पीएमओ ने चिंता जाहिर की है। राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल की शुक्रवार को बैठक हुई। अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्र ने कहा कि मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए।

धूल नियंत्रण के पर्याप्त उपाय जरूरी : मिश्र

बैठक में डॉ. मिश्र ने वायु गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़कों और निर्माण दोनों गतिविधियों में धूल नियंत्रण के पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सड़कों के मध्य स्थित जगहों को हरा-भरा करने और धूल से बचने के लिए पैदल पथों और सड़कों के किनारे खुले क्षेत्रों को पक्का करने या हरा-भरा करने पर मिशन मोड में काम करने का आग्रह किया।

उन्होंने लैंडफिल साइटों की निकासी की धीमी गति और नगर निगम द्वारा कचरे से बिजली बनाने की योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी पर चिंता जताई। बैठक में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक उपायों को लागू करने में दिल्ली सरकार और अन्य हितधारकों की तत्परता का आकलन किया गया। दिल्ली के मुख्य सचिव ने वर्ष 2024 के लिए शहर की वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रयासों पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से निर्माण संबंधित धूल, बायोमास जलाने और वाहन से होने वाले उत्सर्जन का वायु प्रदूषण में योगदान बना हुआ है। मौसम के कारकों के चलते खासकर सर्दियों में हालात ज्यादा बिगड़ जाते हैं। बैठक में एमओएचयूए सचिव, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, डीडीए, एनडीएमसी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग समेत तमाम विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

नाले का सौंदर्यीकरण एलजी ने किया : डीडीए

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। डीडीए ने द्वारका में एक नाले के सौंदर्यकरण के मामले में श्रेय लेने पर आम आदमी पार्टी को घेरा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को कहा कि द्वारका के नाले का सौंदर्यकरण उपराज्यपाल ने किया है। आम आदमी पार्टी इस पर गलत तरीके से श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल ने फरवरी 2024 में ही कर दिया था। प्राधिकरण ने इस संबंध में फोटो भी जारी किए हैं। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि यही नहीं, पूरे शहर में डीडीए द्वारा विकास के अनेक कार्य किए जा रहे हैं जिसका श्रेय आम आदमी पार्टी अथवा किसी और द्वारा लेना उचित नहीं है।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 12 अक्टूबर 2024

केंद्र के कार्यों को अपना बता रही है सरकार : विजेंद्र

■ प्रस, नई दिल्ली : द्वारका में नाले के ब्यूटिफिकेशन वर्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता यह दावा कर रहे है कि काम दिल्ली सरकार ने कराया है, जबकि डीडीए नाले के ब्यूटिफिकेशन वर्क पर अपना दावा कर रहा है। विवाद पर नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। आम आदमी पार्टी तो हर सीमा लांघ चुकी है। जिस काम को केंद्र सरकार ने कराया है, अब उसे अपना बता रही है। वास्तव में आप आदमी पार्टी सरकार के पास लोगों को दिखाने के लिए कोई काम ही नहीं है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई काम ही नहीं कराया है।

गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन डीडीए ने द्वारका में नाले को ढक कर उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन वर्क कराया था। आम आदमी पार्टी नेता इस ब्यूटिफिकेशन वर्क की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे कराने का क्रेडिट दिल्ली सरकार को दे रहे है, जो सरासर झूठ है। आम आदमी पार्टी के विडियो पर

नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता

डीडीए अधिकारियों ने प्रतिक्रिया भी दी है और कहा है कि यह विकास कार्य दिल्ली सरकार ने नहीं, बल्कि डीडीए ने कराया है जो केंद्र सरकार के अधीन है। गुप्ता ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए एलजी वीके सक्सेना ने डीडीए अधिकारियों को निर्देश दिया था। फरवरी, 2024 में एलजी ने प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। यह शर्म की बात है कि आम आदमी पार्ट सरकार के पास लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो वह केंद्र सरकार के कार्यों पर श्रेय लेने की असफल कोशिश कर रहे है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2024 ----DATED----

पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने **उच्चस्तरीय कार्य बल** की बैठक में दिए निर्देश

लैंडफिल साइटों को जल्द करें खत्म

लाला दीक्षित • जागरण

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कार्य बल की बैठक हुई। इसमें दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की समीक्षा हुई। बैठक में ठोस कचरे का मुद्दा प्रमुखता से उठा। पीके मिश्रा ने खुले में कचरा और बायोमास जलाने पर रोक लगाने को कहा क्योंकि सर्दियों में ये प्रदूषण बढ़ाने का मुख्य कारक होते हैं। पीके मिश्रा ने लैंडफिल साइटों को खत्म करने और निगम के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की धीमी रफ्तार पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने शहरी विकास व पर्यावरण मंत्रालय एवं नगर निगम को विशेष तौर पर इन कार्यों में तेजी लाने और समस्या का हल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में पराली जलने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने पर भी चर्चा हुई। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने और चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की बात हुई।

कार्य बल में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि, शहरी विकास व पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, दिल्ली पुलिस, नगर निगम, डीडीए, एनडीएमसी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रतिनिधि शामिल थे। निर्माण गतिविधियों की धूल, कचरा व बायोमास जलना और वाहनों का धुआं दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुख्य कारक बताए गए और इसे नियंत्रित करने के हो रहे उपायों की जानकारी दी गई। पीके मिश्रा ने दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता बने रहने पर चिंता जताई और मौजूदा कानूनों को कड़ाई से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्माण स्थलों और सड़क पर धूल से निपटने के ठोस उपाय करने की बात कही।

निराशाजनक स्थिति >> संपादकीय

ओखला लैंडफिल साइट पर जमा कूड़ा • जागरण आर्काइव

- पीके मिश्रा ने खुले में कचरा और बायोमास जलाने पर रोक लगाने को भी कहा
- दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता बने रहने पर जताई चिंता

लैंडफिल साइट	2019 में कूड़ा	अब कितना बचा
गाजीपुर	140	82.60
भलस्वा	80	47.66
ओखला	60	29.61
कुल	280	159.87

आंकड़े लाख मीट्रिक टन में

वाहन, धूल व बायोमास जलाने से वायु गुणवत्ता में गिरावट

नई दिल्ली: वाहन, सड़क की धूल, निर्माण धूल, बायोमास जलाना और औद्योगिक उत्सर्जन सर्दियों के महीनों में दिल्ली के वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। यह जानकारी शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सामने आई है।

विस्तृत >> पेज 8

बड़े क्षेत्र में निर्माण पर एंटी स्माग गन जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: एनसीआर के वायु प्रदूषण में निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों का काफी असर होता है। लिहाजा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश जारी कर रखे हैं, जिसके मुताबिक न सिर्फ 500 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र में निर्माण का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, बल्कि बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी स्माग गन लगाना भी जरूरी है। जितना बड़ा निर्माण क्षेत्र होगा, उतनी ज्यादा संख्या में एंटी स्माग गन लगाई जाएंगी, ताकि प्रदूषण न बढ़े। ये बात वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों पर सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में कही है।

एक अक्टूबर को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, 5,000 से 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण पर एक एंटी स्माग गन लगाना जरूरी है। यदि निर्माण क्षेत्र 10,001 से लेकर 15,000 वर्ग मीटर है तो दो, 15,001 से 20,000 वर्ग मीटर तक तीन और 20,001 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण क्षेत्र में चार एंटी स्माग गन लगाना जरूरी है।

दिल्ली में 583, यूपी में 800 व हरियाणा में 737 बड़े निर्माण हैं दर्ज

>> पेज 8

निराशाजनक स्थिति

दिल्ली में लैंडफिल साइटों में बने कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में हो रही देरी पर प्रधानमंत्री कार्यालय का गंभीर चिंता जताना सर्वथा उचित है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक लेते हुए पीएमओ में प्रधान सचिव ने लैंडफिल साइटों से कूड़ा खत्म करने और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने के कार्य की धीमी गति पर संबंधित एजेंसियों को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने धूल नियंत्रण, कूड़े के बेहतर निस्तारण, कूड़ा जलाने से रोकने और फुटपाथ पर हरियाली करने व फर्श बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारियों को लेकर किए जा रहे तात्कालिक और दीर्घकालिक उपायों की समीक्षा भी की।

> यह समझा जाना चाहिए कि यदि नियंत्रण के ठोस उपाय किए जाएं तो प्रतिकूल स्थितियों में भी वायु प्रदूषण दिल्ली को बहुत परेशान नहीं कर पाएगा

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन निराशाजनक है कि ये प्रयास बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं। वायु प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए नए तरीके के प्रयासों की आवश्यकता है। यह सही है कि सर्दी के दिनों में मौसम की स्थितियों के कारण हवा की गति कम हो जाती है और वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिससे प्रदूषक तत्व वायुमंडल में ऊपर नहीं जा पाते और प्रदूषण गहराता है, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि यदि नियंत्रण के ठोस उपाय किए जाएं तो ऐसी स्थितियों में भी वायु प्रदूषण दिल्ली को बहुत परेशान नहीं कर पाएगा।

दिल्ली में 583, यूपी में 800 व हरियाणा में 737 बड़े निर्माण पोर्टल पर हैं दर्ज

पूर्वत पृष्ठ से आगे

आयोग ने सभी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों का नियमित दौरा करें और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। वेब पोर्टल के अनुसार 31 अगस्त तक दिल्ली में 583, उत्तर प्रदेश में 800, हरियाणा में 737 और राजस्थान में 144 बड़े निर्माण पोर्टल पर दर्ज हैं। नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई का ब्योरा देते हुए आयोग ने बताया है कि दिल्ली में 20,806 निर्माण स्थलों का मुआयना हुआ, जिसमें से 1,213 में नियमों का उल्लंघन मिला और पर्यावरण क्षतिपूर्ति का आदेश हुआ। हरियाणा में 1,485 स्थलों में 90 पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति और 150 पर काम रोकने का आदेश हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 983 में से 104 पर उल्लंघन पाया गया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2024 दैनिक जागरण ATED----------

नाले का सुंदरीकरण 'आप' ने नहीं, एलजी ने किया : डीडीए

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें द्वारका में एक नाले के आसपास सुंदरीकरण का काम पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा कराए जाने का जिक्र किया गया था। डीडीए ने कहा कि यह परियोजना उपराज्यपाल ने पूरी कराई है।

आप ने 'एक्स' पर द्वारका के एक नाले के आस-पास के क्षेत्र के सुंदरीकरण से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद डीडीए ने बयान जारी किया। वीडियो में पार्टी ने दावा किया कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नाले के आस-पास

द्वारका में नाले के पास किए गए सुंदरीकरण का श्रेय लेने की लगी होड़ • सौजन्य-एक्स

के क्षेत्र का इस तरह से सुंदरीकरण कर सकते हैं। डीडीए ने भी एक्स पर एक पोस्ट में आप के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का पोस्ट में किया गया दावा 'नाले वाली जगह का अरविंद केजरीवाल द्वारा सुंदरीकरण' सरासर गलत है। यह काम उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नेतृत्व में डीडीए की ओर से किया गया है। इसका उद्घाटन एलजी ने फरवरी 2024 में ही कर दिया था। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि यही नहीं, पूरे शहर में डीडीए द्वारा विकास के अनेक कार्य किए जा रहे हैं जिसका श्रेय आम आदमी पार्टी व किसी और द्वारा लेना उचित नहीं है।

उधर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को आप अपनी उपलब्धि बता रही है। वीडियो बनाते समय आप नेताओं को जरा भी संकोच नहीं हुआ।

विधानसभा चुनाव नजदीक देखकर वह जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मेट्रो विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, आयुष्मान योजना सहित नरेन्द्र मोदी सरकार की अन्य योजनाओं में आप सरकार रोडा अटकाती है। बाद में उसे अपनी उपलब्धि बताती है। दिल्लीवासी अब उनके झांसे में नहीं आएंगे।

दुर्गा पूजा पर मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार किया कृत्रिम घाट

गुलाबी बाग में तैयार किया गया कृत्रिम घाट • सौजन्यः जिला प्रशासन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दुर्गा पूजा पर यमुना में मूर्ति विसर्जन रोकने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है, चूंकि यमुना का इलाका ज्यादातर मध्य और नई दिल्ली जिला प्रशासन के साथ ही पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन की सीमा में लगता है। इसलिए इन सभी जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही लोगों से अपील की है कि लोग केवल तय स्थान पर ही दुर्गा मूर्ति का विसर्जन करें। अगर, कृत्रिम तालाबों के अलावा कहीं कोई मूर्तियों का विसर्जन करते पकड़ा जाता है, तो उसे एनजीटी के दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माने या फिर कारावास की सजा हो सकती है।

नई दिल्ली जिला प्रशासन ने दो तो मध्य दिल्ली जिला प्रशासन ने चार स्थानों पर कृत्रिम तालाब बनवाएं है। मध्य दिल्ली जिला प्रशासन ने डीडीए पार्क, पेट्रोल पंप के पास गुलाबी बाग में, सुनील कालोनी बुराड़ी, यमुना पुस्ता ठोकर नंबर 2 और खसरा नंबर 29/21 उत्तराखंड कालोनी बुराड़ी में कृत्रिम तालाब विकसित किए जा चुके हैं। जहां पर नागरिक विसर्जन कर सकते हैं। वहीं, नई दिल्ली जिला प्रशासन पंडारा पार्क और कालीबाड़ी मार्ग में कृत्रिम तालाब है।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 12 अक्टूबर 2024

नाले किनारे ब्यूटिफिकेशन के दावे को डीडीए ने बताया गलत

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली: डीडीए ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के उस दावे को गलत बताया जिसमें उसने द्वारका ड्रेन एरिया के ब्यूटिफिकेशन का काम अरविंद केजरीवाल की निगरानी में होने की बात की है। डीडीए ने साफ किया कि द्वारका ड्रेन के किनारों की ब्यूटिफिकेशन का यह काम एलजी की निगरानी में हुआ है। आप ने अपने एक्स हैंडल पर एक द्वारका का एक विडियो पोस्ट किया। पोस्ट में द्वारका ड्रेन एरिया के ब्यूटिफिकेशन की बात की गई थी। पार्टी ने दावा किया कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल (आप के मुखिया और पूर्व सीएम) ही ड्रेन एरिया में ऐसा ब्यूटिफिकेशन का काम कर सकते है।

आप ने लिया था क्रेडिट, डीडीए ने कहा- एलजी ने कराया काम

इस विडियो के जारी होने के बाद डीडीए ने एक्स पर पोस्ट कर इस दावे का खंडन किया। इसमें कहा गया कि नाले वाली जगह का आरविंद केजरीवाल द्वारा ब्यूटिफिकेशन सरासर गलत है। यह काम एलजी विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में डीडीए द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन एलजी ने फरवरी 2024 में ही कर दिया था। यही नहीं, पूरे शहर में डीडीए द्वारा विकास के अनेक कार्य किए जा रहे है। इसका श्रेय आम आदमी पार्टी अथवा किसी और द्वारा लेना उचित नहीं है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times NEW DELHI MONDAY OCTOBER 14, 2024

Boats, pontoons, bridges: Linking a city split by a river

With Delhi weeks away from getting a new railway bridge across the Yamuna, a look at the history and need for traversing the iconic river

Paras Singh
paras.singh@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Old Iron Bridge, known colloquially by its Hindi name Lohe ka Pul, was the first modern bridge to be built across the Yamuna, opening for public use in 1866. The double-deck bridge caters to vehicular traffic on the lower deck, and a two-lane railway line on the upper deck, connecting the Old Delhi railway station to the Shahdara railway station.

Lohe ka Pul caters to around 200 trains entering or exiting Delhi daily, and every year during monsoon, the movement of trains is slowed down as the Yamuna comes into spate. In 1998, a new railway bridge running parallel to Lohe ka Pul was envisaged to take the load off the existing structure, and construction began in 2003.

After decades of delays, the new bridge is likely to open for rail traffic in November.

"There are currently two railway bridges that are operational — Lohe ka Pul and Tilak bridge-Anand Vihar bridge. The work on the new bridge will be completed by October-end, and should be ready for use in November. Another bridge in the form of two more lines parallel to Tilak bridge-Anand Vihar line has also been proposed," a Northern Railways official said, on condition of anonymity.

Around 46km of the Yamuna flows through Delhi, and at present, 15 functional bridges traverse its width — three barrages to control the flow of the river, two railway bridges, four Metro bridges, and six for cars. These serve as key connectivity points for trans-Yamuna areas, which house more than a third of the city's population despite being just 7.13% of its area.

The new structure, coming up between the Wazirabad barrage and the Signature Bridge, is set to be the 16th functional bridge across the river.

The history of bridges in Delhi

During the Mughal era, areas that today consist of trans-Yamuna localities were hunting grounds for the nobility — this region was reached by crossing the river on elephants. Soon afterwards, these grounds were connected to Red Fort and Salimgarh via a "bridge of boats" — a bridge made up of wooden boards.

Author Narayani Gupta, in her book Delhi Between Two Empires: 1803-1931,

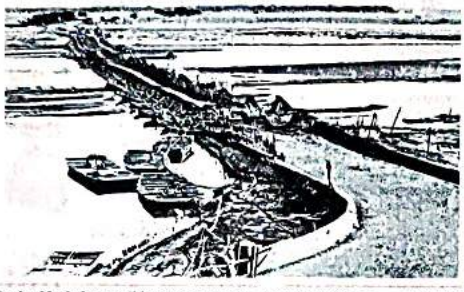

During Mughal era, Delhi got its first bridge – the bridge of boats. COURTESY: ASI

wrote that before 1857, the only way to approach Delhi from the east was by crossing this "bridge of boats".

However, the 1857 rebellion changed everything. The rebellion — and a paranoia about its recurrence — convinced the British to construct a structure traversing the river, connecting Calcutta — the then capital — to Delhi. "Myths are often more real than facts, and the image of Delhi's 'inflammable population' was very real to the British," Gupta wrote.

Construction of the double-decked steel truss bridge connecting central Delhi to Shahdara began in 1863 and finished in 1866. The East India Railway spent £1,616,335 — equivalent of approximately ₹1,900 crore in today's money — on it.

Swapna Liddle, the author of Chandni Chowk: The Mughal city of Old Delhi, wrote that the railway came to Delhi with the first train steaming in on New Year's Eve of 1867. "The railway line was built across the northern half of the city, cutting the city in two. It necessitated the demolition of many houses, and the owners of which were compensated with property confiscated after the revolt," she wrote.

The Wazirabad barrage was built in 1959, followed by the ITO barrage in the 1960s. AK Jain, former commissioner (planning) at Delhi Development Authority (DDA), said that the primary purpose of was the regulation of the flow of the Yamuna — traffic was only secondary. "These barrages were not designed for connectivity," he said.

The 'neglected' trans-Yamuna

The construction of the Wazirabad and ITO barrages *led to a population surge in Delhi, with areas such as Laxmi Nagar, Shakarpur, Preet Vihar and Swasthya Vihar coming up.* Later, the Nizamuddin bridge, built in the 1970s as a four-lane bridge before being widened in 1998, fuelled growth in areas such as Mayur Vihar, Trilokpuri, and beyond.

Jain said that the heavily populated areas of east Delhi have faced discrimination in the form of lack of bridges and connectivity, noting that more than 3.5 million people live here, if one goes by numbers just from the 2011 census.

"In modern European cities, there is a bridge on an average of 1.5-2km, and Delhi, with a much higher population base, needs more bridges," Jain said.

Of the 15 bridges in Delhi that are currently operational, only Lohe Ka Pul caters to two types of traffic — rail and vehicular. Jain said that shows a lack of foresight in planning. "If the Britishers could have planned a dual use bridge in the 19th century, we should have developed double-decker bridges for Metro systems as well vehicular movement," he said.

BS Vohra, who heads the East Delhi RWA joint front, said that in the early days there were only two bridges for commuters. "Lohe ka Pul was our main lifeline, and the ITO barrage carriageway, was only a two-lane road. In addition, Geeta Colony had a pontoon bridge, which had to be closed during the monsoon," he said.

Another bridge across the Yamuna acts as a major lifeline for Noida and beyond. The Delhi-Noida Direct Flyway or DND Flyway — India's first eight-lane access-controlled expressway — opened for traffic in January 2008.

The most iconic bridge in Delhi — the Signature Bridge, which connects Wazirabad to the inner city — is "India's first asymmetrical cable-stayed bridge", according to Delhi government, which shortens the travel time between north Delhi, and northeast Delhi and Ghaziabad.

The bridge finds its origin in the 1997 Wazirabad bus tragedy, when a school bus carrying students of Ludlow Castle plunged into the Yamuna from the Wazirabad bridge, killing 28 children. "The accident led to the demand of a better, wider bridge," a PWD official said.

The way ahead

At present, there are four bridges under construction — a Metro bridge near Sur Ghat, part of the Pink Line; the new railway line near Lohe ka Pul; Barapullah bridge phase 3; and a bridge being built for the Regional Rapid Railways System (RRTS) line between Sarai Kale Khan and Meerut.

The railways official quoted above said that a second bridge is planned parallel to the Anand Vihar line to add two more sections. "There are two bridges proposed in Delhi—the new bridge over the Yamuna in lieu of Old Yamuna Bridge and a second one between Anand Vihar and Tilak Bridge which will be third and fourth line on the same alignment," the official said.

In addition, PWD has some plans in the pipeline. "The East-West corridor, which will provide signal-free connectivity from Anand Vihar in the east to Tikri in the west, will have a bridge component downstream of the new railway bridge at Nizamuddin. The project is currently stuck due to land-sharing issues," a PWD official said.

Three more bridges in northeast Delhi were proposed 10 years ago. "These projects, with a combined cost of ₹1,496 crore, have been approved by Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning & Engineering) Centre, but are lying in cold storage," a PWD official said.

Dr S Velmurugan, chief scientist and head of traffic engineering and safety division at Central Road Research Institute (CRRI), said that Delhi has around 250 vehicles per 1,000 people and the number will only go up in future, for which the city needs more bridges.

"If the Old Railway Bridge could be planned to cater to dual mode so many years back, the newer bridges being built by Delhi Metro and other agencies should have been planned in a way that they could cater to vehicles as well. Delhi needs more bridges, and every agency is making plans to cater to its own needs. We need a more integrated approach," Dr Velmurugan said.

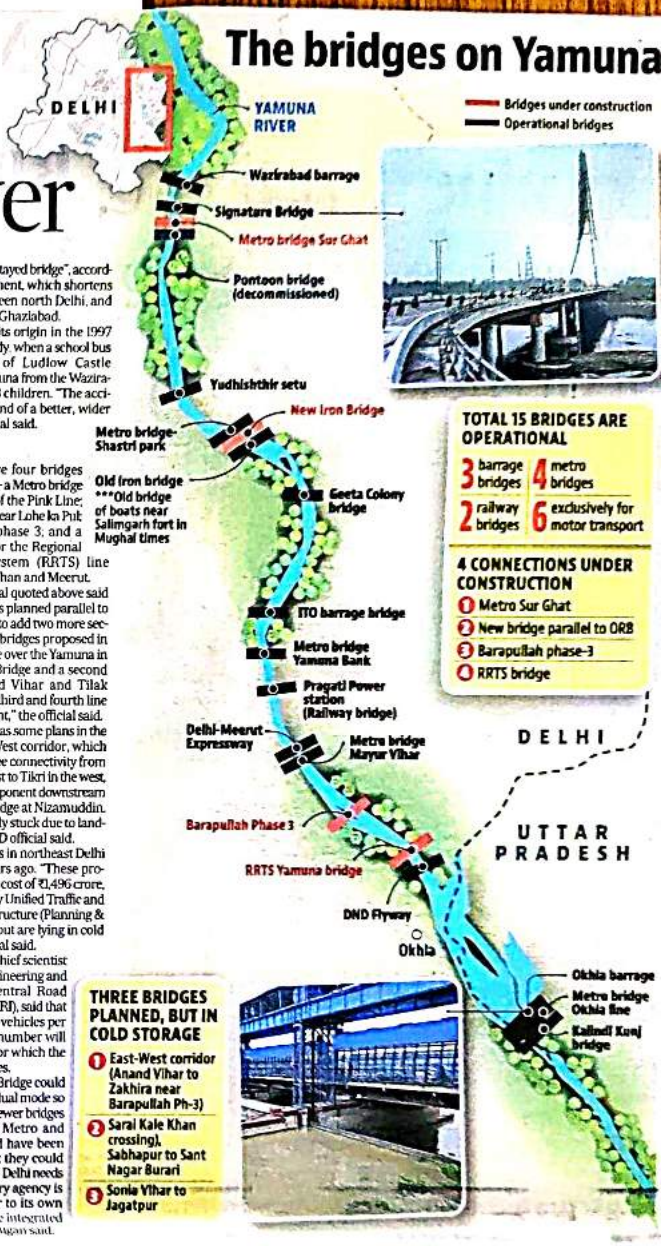

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- Hindustan Times NEW DELHI MONDAY OCTOBER 14, 2024

{ TO BE INAUGURATED BY NOV-END }

Dwarka golf course, the longest in India, to open memberships soon

Snehil Sinha
snehil.sinha@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Dwarka golf course, the longest in the country, in Sector 24 is likely to be opened for memberships next week, Delhi Development Authority (DDA) officials said.

Meanwhile, the work at the golf course is nearly complete and it will likely be inaugurated by the end of November, the officials added.

Spread over 159 acres, the 18-hole golf course has a total length of 7,377 yards. Officials from DDA said that until now, the longest golf course in the country was the Jaypee golf course in Greater Noida, which has a length of 7,374 yards, followed by Chandigarh golf course with a length of 7,202 yards.

"We will initially open tenure membership of three or five years for 1,200 people. Depending on the response, the members may be increased later. The fee is yet to be decided but it is expected to be similar to Qutab golf course. We plan to start the application process by next week," said a DDA official.

The new golf course will also have one of the longest driving ranges in the country with a total length of 372 yards. The double-decker driving range will have 52 bays for golf carts across two floors. A golf academy will also be established to train young and budding golfers, officials said.

The 18-hole golf course has a total length of 7,377 yards. HT PHOTO

A separate nine-hole course is also being developed for short games and practice sessions. Audio-visual simulation rooms can be used for training children and night lights will also be available, though there are no plans to start night golfing as of now, officials said. A six-hole 'Chip and Putt' course for children and young aspirants has also been made.

"There will also be a luxury club with great F&B facilities, snack bar, lecture room, fitting room, club house. This will be a zero-discharge facility where all sewage will be treated at the two treatment plants having a capacity of 60 MLD each," said Colonel (retired) Sanjay Sharma, secretary of the Dwarka golf course.

The golf course is also expected to have features such as capillary bunkers and Bermuda grass that is being used for the first time in the country, officials added. DDA said it will also be using the course for public championships in the future.

Another official said while the MiniVerde grass is being used for the greens, North Shore SLT will be used for the fairway.

"For the first time in the country, we are using MiniVerde grass, considered to be one of the best for golf courses. It has a straight vertical growth and can be cut very fine unto 2.5mm. If the grass is taller, it changes the line of the ball. Also, the capillary bunkers with wood cladding that we have used is only second to the Karnataka Golf Association's course in Bangalore. These bunkers are more porous and get dried easily," said a senior DDA official.

Officials said there is also a parking space for 180 vehicles, while parking outside along the service roads will be allowed too. A 15-acre land towards the north of the golf course has also been kept for expansion of commercial and shopping activities.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2024

14 अक्टूबर 2024
हिन्दुस्तान

NAME OF NEWSPAPERS---------- ----DATED----------

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर झुग्गीवासियों को मिला न्याय

- हाई कोर्ट ने डीडीए व डूसिब को दिया जंगपुरा की झुग्गी के 43 पूर्व निवासियों के पुनर्वास का निर्देश
- डीडीए के वर्ष 2015 में जारी आदेश को रद करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया निर्णय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: वर्ष 2015 में जंगपुरा-बी में एक झुग्गी को बिना किसी नोटिस के ध्वस्त करने के मामले में पुनर्वास से इन्कार करने के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली हाई कोर्ट ने 43 पूर्व निवासियों के पक्ष में निर्णय सुनाया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की कार्रवाई को सोच वाला करार देते हुए कहा कि सत्यापित राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और वर्ष 2004 में स्लम और जेजे विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण से सभी याचिकाकर्ताओं के विवादित स्थान पर लंबे समय से रहने की पुष्टि होती है। न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने इस टिप्पणी के साथ डीडीए व दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) को 43 पूर्व निवासियों का पुनर्वास करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही 31 जनवरी 2015 को संयुक्त बैठक में डीडीए व डूसिब द्वारा लिए गए निर्णय को भी रद कर दिया।

अदालत ने यह टिप्पणी व निर्देश याचिककार्ता जियाउल हक की अपील याचिका पर दिया। जियाउल हक ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है।

आठ नवंबर 2006 को एमसीडी और डीडीए द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर दिए बिना झुग्गियों को ढहा दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि 500 से अधिक परिवार दो दशकों से अधिक समय से जंगपुरा बी में डीबीएस कैंप में रह रहे हैं। इस निर्णय के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने पुनर्वास की मांग की थी, लेकिन डीडीए व डूसिब ने याचिकाकर्ताओं की मांग को ठुकरा दिया था।

फ्लैट की जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं

डीडीए की पहले आओ पहले पाओ आवासीय योजना में कई फ्लैटों के पंजीकरण और बुकिंग प्रक्रिया जारी है। फ्लैटों के बारे में जानकारी के लिए कॉल सेंटर नंबर 1800110332 पर कॉल कर सकते हैं। इस संबंध में डीडीए के नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया गया है।

अगर न हो समस्या का हल

दैनिक जागरण आपके मुद्दों को उठा रहा है। अगर, आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के हेल्पलाइन नंबर 1800110332 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं दक्षिण दिल्ली नगर निगम कार्यालय के दूरभाष नंबर 011- 47501986 के साथ ही दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर भी फोन कर सकते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI OCTOBER 13, 2024 -----DATED----------

AAP seeks probe into 'illegal sale' of DDA's flats in Kalkaji, BJP hits back

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Urban development minister **Saurabh Bharadwaj** alleged on Saturday that the Delhi Development Authority housing units meant for slum dwellers in south Delhi's Kalkaji were being sold illegally to ineligible individuals. Referring to a sting operation by a private news channel, Bharadwaj claimed that such a big scam was happening right under the nose of the lieutenant governor and it wasn't possible that VK Saxena was not aware of it.

While DDA called the allegations levelled by Bharadwaj and the TV channel "patently false, without any basis and bereft of facts", Delhi BJP president Virendra Sachdeva accused the minister of spreading misinformation against central agencies.

Addressing a press conference, Bharadwaj alleged that selling the flats to ineligible individuals undermined the very purpose of the initiative. "Over the past two years, central govt agencies demolished jhuggis and rendered lakhs of people homeless. They are forced to live under flyovers, pedestrian overbridges and along the banks of drains. These displaced people are supposed to receive these flats," the minister added.

Calling for an independent investigation into the matter, Bharadwaj said only a sitting Supreme Court or high court judge could ensure transparent inquiry.

"If the Anti-Corruption Branch or CBI investigate, the scam will likely be covered up since these agencies work under LG and central govt," he claimed.

DDA claimed that not a single dwelling unit in the Kalkaji slum rehabilitation project had been allotted to an ineligible beneficiary. It claimed to have "foolproof technology-enabled systems" in place to avoid fraudulent allotment. "Not a single person recorded in the supposed 'sting' operation by the news channel is even remotely associated with DDA, leave apart being its employee, as is being claimed," DDA said in a statement. "A police complaint has already been filed against the individuals shown as black marketers in the supposed sting operation."

DDA alleged that a preliminary inquiry revealed that the black marketers were associated with a political party and were working with the sole purpose of defaming the authority and its hugely popular and successful slum rehabilitation scheme.

BJP's Sachdeva also questioned Bharadwaj, asking why the Kejriwal govt left 40,000 flats, built under the Rajiv Awas Yojana in Narela and Bawana during Sheila Dikshit's tenure, to go to seed without allocating them to beneficiaries. He accused the AAP govt of failing to implement the Pradhan Mantri Awas Yojana in Delhi, leaving many poor families without a roof over their heads.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- Hindustan Times NEW DELHI SUNDAY OCTOBER 13, 2024

{ DDA BIODIVERSITY PARKS } MOST BUTTERFLIES OBSERVED IN ARAVALLI PARK

68 butterfly species found during annual count

Aheli Das
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: This year's butterfly count, which looked at the variety of the insects across the seven biodiversity parks that fall under the jurisdiction of the Delhi Development Authority (DDA), has recorded 8,337 individuals across 68 species in these green spaces, people who took part in the exercise between October 8 and 10 said on Saturday.

The census — a joint initiative by DDA and Delhi University (DU) — has been an annual three-day affair over the past six years, and is conducted across the Yamuna, Aravalli, Tilpath Valley, Northern Ridge, Neela Hauz, Tughlaqabad, and Kalindi biodiversity parks.

The highest number of butterfly species were observed in the Aravalli park, at 58, while the least —18 —were found in Kalindi.

"Butterflies from all five families — Papilionidae, Pieridae, Lycaneidae, Nymphalidae, Hesperiidae — were observed in the parks," Faiyaz Khudsar, the scientist in-charge of the biodiversity parks programme, said.

During the survey, participants observed several common butterflies, such as the plain tiger and the common emigrant. Some intercontinental travellers too were found during the survey.

"The painted lady is a migrant butterfly which comes from cold European countries such as England and Ireland, passes through Delhi, and then migrates southwards to warmer places as butterflies are cold blooded and need warmer weather. It migrates back to the west in February-March," Aisha Sultana, a wildlife ecologist and a senior scientist from the biodiversity parks programme, said.

Surya Prakash, a retired professor from the School of Life Sciences, Jawaharlal Nehru University, said that though there are over 100 species of butterflies in Delhi at present, the ones observed have changed over the past two decades.

"A 2002 paper by Torben B. Larsen mentions 86 butterfly species observed in Delhi but many of them are not found now, the major reason being urbanisation and loss of habitat. One such species is Black Rajah," Prakash mentioned.

Findings of the count

8,337 Individuals

68 Species

TOP SPECIES (by population size)

- Plain tiger
- Common emigrant
- Yellow orange tip
- Lemon pansy
- Common gull
- Common grass yellow

58 The highest number of butterfly species were spotted in the Aravalli park, while the least, 18, were observed in Kalindi.

Minister: Graft in DDA's EWS flats

NEW DELHI: Aam Aadmi Party (AAP) leader and Delhi minister Saurabh Bharadwaj on Saturday accused the Delhi Development Authority (DDA) of selling flats meant for 'jhuggi' dwellers under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) on the black market. Speaking at a press conference on Saturday, Bharadwaj referred to a recent "sting operation" which claimed that the flats were being sold to ineligible buyers.

"There's a lengthy process for a 'jhuggi' dweller to be allotted a flat... Yet, people with no such documentation are being allotted these flats," he added.

Bharadwaj also alleged that such corruption was likely happening with the knowledge of senior DDA officials and the lieutenant governor, who chairs the DDA.

Responding, the DDA called the allegations "baseless" in a statement and said no flats had been illegally sold. The DDA added that a police complaint has been filed against individuals shown in the sting and promised to pursue legal action. HTC

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- हिन्दुस्तान नई दिल्ली रविवार, 13 अक्तूबर 2024 --------DATED----------

बेचे जा रहे झुग्गीवासियों के फ्लैट: सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डीडीए की ओर से झुग्गी की जगह दिए जाने वाले फ्लैटों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को कहा है कि एक स्टिंग ऑपरेशन में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। झुग्गीवासियों को मिलने वाले फ्लैट ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जो इसके पात्र ही नहीं है।

उन्होंने कहा कि डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है। इस मामले में जज की अध्यक्षता में जांच करवानी चाहिए। दिल्ली में झुग्गियों को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद दिल्ली से झुग्गियों को हटाना था ताकि दिल्ली को सुंदर और साफ बनाया जा सके। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने खुद कालकाजी स्थित फ्लैटों का उद्घाटन किया था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा हमेशा गरीबों के खिलाफ नजर आती है। दिल्ली सरकार ने गरीबों को मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा दी तो भाजपा ने इसका विरोध किया। भाजपा की अलग-अलग एजेंसियों ने दिल्ली में झुग्गियों को तोड़कर लाखों लोगों को बेघर किया है। तुगलकाबाद, महरौली, सरोजिनी नगर और सफदरजंग एयरपोर्ट के पास हजारों झुग्गियों को तोड़कर लोगों को बेघर किया गया।

आमने-सामने

एक भी आवास का आवंटन गलत नहीं हुआ : डीडीए

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ऑपरेशन मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को भारद्वाज ने डीडीए समेत एलजी पर कई आरोप लगाए थे। डीडीए ने भारद्वाज के फ्लैटों को गलत तरीके से आवंटित करने के आरोपों को गलत बताया।

डीडीए प्रशासन ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के आरोप स्पष्ट रूप से झूठे, बिना किसी आधार और तथ्यों के तहत दिए गए हैं। कालाकाजी स्लम पुनर्वास परियोजना में एक भी फ्लैट व आवास किसी आयोग्य लाभार्थी को आवंटित नहीं किए गए। डीडीए के पास यह सुनिश्चित करने के लिए फुलप्रूफ प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली है जिसे कोई फर्जी आवंटन व बिक्री न हो। एक समाचार चैनल के कथित स्टिंग ऑपरेशन में दर्ज एक भी व्यक्ति डीडीए से दूर-दूर तक जुड़ा हुआ नहीं है।

पुलिस के साथ मिलकर मामले को आगे बढ़ाएंगे : डीडीए ने कहा कि इस मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगा। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फ्लैटों की कालाबाजारी करने वाले एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। यह डीडीए को बदनाम करने के एक पक्षपातपूर्ण उद्देश्य से पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र के उस राजनीतिक दल के एक नेता के इशारे पर काम कर रहे हैं।

तितलियों की 68 प्रजाति पाई गईं

नई दिल्ली। राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में डीडीए की ओर से संचालित जैव विविधता पार्कों में तितलियों की 68 प्रजातियां पाई गई हैं। शनिवार शाम को तितली गणना के नतीजे घोषित किए गए। वैज्ञानिक प्रमुख फैयाज खुदसर ने बताया कि अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में सबसे ज्यादा 58 और कालिंदी जैव विविधता पार्क में सबसे कम 18 प्रजातियां रिकॉर्ड की गई हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- । संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली
। 13 अक्टूबर 2024 -DATED----------

गरीबों के घरों पर राजनीति तेज़

झुग्गीवालों के फ्लैट ब्लैक में बेचे जा रहे हैं: सौरभ

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि झुग्गी के बदले मिलने वाले फ्लैट को ब्लैक में बेचा जा रहा है। सौरभ ने कहा कि यह बेहद ही अफसोसजनक और आश्चर्य की बात है कि जिन फ्लैटों का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उन फ्लैटों को एक बड़े भ्रष्टाचार के तहत ब्लैक में उन लोगों को बेचा जा रहा है, जो लोग झुग्गी बस्ती में रहने वाले नहीं है।

दिल्ली के मंत्री ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

सौरभ ने कहा कि बड़ा प्रश्न यह उठता है कि बीजेपी हमेशा गरीबों के खिलाफ क्यों नजर आती है? जब भी कभी गरीबों की भलाई का कोई काम होता है, तो बीजेपी हमेशा इसकी खिलाफत करती क्यों नजर आती है? उन्होंने कहा कि जब दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 20 हजार लीटर मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की, तो बीजेपी ने सभी योजनाओं की खिलाफत की थी और अब जो फ्लैट गरीबों के लिए बनाए गए थे, वही फ्लैट ब्लैक में अन्य लोगों को बेचे जा रहे है।

सौरभ ने कहा कि पिछले दो साल में हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार की डीडीए, रेलवे, एलएनडीओ और एएसआई आदि ने अलग-अलग क्षेत्र में बसी लिस्टेड क्लस्टर एरिया को उजाड़ा और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। यह वही लिस्टेड क्लस्टर एरिया थे, जिनको झुग्गी के बदले फ्लैट मिलना था। केंद्र सरकार और उसके अधीन आने वाली एजेंसियों ने जबरदस्ती इन झुग्गियों को उजाड़ दिया और अब इनको मिलने वाले फ्लैटों को ब्लैक में बेचा जा रहा है। आप नेता ने कहा कि यह सीधे-सीधे एक भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है कि जिन क्लस्टर एरिया को उजाड़ा गया, अब वह लोग दूसरी जगह पर जाकर झुग्गियां बसा रहे है। फिर दोबारा से उनके नाम पर नए फ्लैट बनाए जाएंगे और उन्हें भी ब्लैक में बेच दिया जाएगा।

डीडीए ने आरोपों को गलत बताया: डीडीए ने कहा कि डीडीए की प्रक्रिया टेक्नॉलजी फूलप्रूफ है और उसमें फ्रॉड की कोई संभावना नहीं है। कथित स्टिंग ऑपरेशन में एक ही व्यक्ति को रेकॉर्ड नहीं किया गया है। डीडीए ने इस फ्रॉड को लेकर पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। डीडीए का कोई अधिकारी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं है।

खंडहर बना दिया गरीबों के सपनों को: सचदेवा

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसे लेकर उन्होंने एलजी और डीडीए दोनों पर निशाना साधा है। जिस पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी पलटवार किया है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने कुछ साल पहले गरीबों को फ्लैट में रहने का सपना बेचा था। गरीबों के सपने अब खंडहर में तब्दील हो गए। सैकड़ों करोड़ की लागत से बने फ्लैट्स जर्जर हो गए है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने किसी गरीब को यह फ्लैट्स नहीं दिए, जबकि यह फ्लैट्स उनके लिए ही बनाए गए थे।

पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी का पलटवार

सचदेवा ने मंत्री सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राजीव रतन आवास योजना के तहत झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को फ्लैट में रहने का सपना बेचा था। योजना के तहत झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकानों में शिफ्ट करने के लिए अलग-अलग जगहों पर 40 हजार से अधिक फ्लैट्स बनाए गए। करीब 16 लाख लोगों ने फ्लैट्स की चाहत में रजिस्ट्रेशन कराया। झुग्गियों में रहने वाले जिन लोगों ने नामांकन कराया, उनमें से कई लोगों ने नाम आने के बाद अपनी कमाई अपने सपनों के मकान लगा दी। बापरौला में बने फ्लैट्स की कीमत 72 हजार और बवाना में फ्लैट्स की कीमत 68 हजार रुपये दिल्ली सरकार ने तय की थी। इन फ्लैटों के लिए इतने पैसे देने के बाद भी लोगों को अबतक फ्लैट्स नहीं मिले है। गरीबों के सपनों के फ्लैट्स अब खंडहर हो गए है। मंत्री सौरभ भारद्वाज उन लोगों को यह क्यों नहीं बताते कि उनकी सरकार की लापरवाहियों के चलते उनके सपनों के मकान खंडहर हो गए।

सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले और गरीबों को पक्का मकान देने का काम दिल्ली सरकार के डूसिब (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड) विभाग का है। लेकिन विभाग ने आजतक किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध कराया। गरीबों के आंसुओं को पोछने का बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया और पीएम आवास योजना के तहत यहां के गरीबों को हाई राइज बिल्डिंगों में पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। इस पर भी आम आदमी पार्टी नेताओं को विरोध है और बिना आधार के आरोप मढ़ रहे है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- । संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 13 अक्टूबर 2024 ----------DATED----------

सातों बायोडायवर्सिटी पार्क में मिलीं 68 प्रजातियों की तितलियां

मॉनसून के बाद भी तेज धूप की वजह से बढ़ते तापमान के बावजूद राजधानी के सातों बायोडायवर्सिटी पार्कों में तितलियां पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। बीते सालों की संख्या में इस साल तितलियों की प्रजातियों में कुछ कमी जरूर आई है। एक्सपर्ट के अनुसार, गर्मी में भी तितलियों का पार्कों में बने रहना यह स्पष्ट करता है कि इन पार्कों में तितलियों के लिए माकूल माहौल तैयार हो चुका है।

राजधानी के सभी बायोडायवर्सिटी पार्क में हुआ तितलियों का आकलन

यह विश्लेषण 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह के तहत किया गया

बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम के इंचार्ज डॉ. फैयाज खुदसर ने बताया कि इस एक हफ्ते के दौरान अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में सबसे ज्यादा 58 और कालिंदी पार्क में सबसे कम 18 प्रजातियां रेकार्ड की गईं।

कहां मिलीं कितनी तितलियां

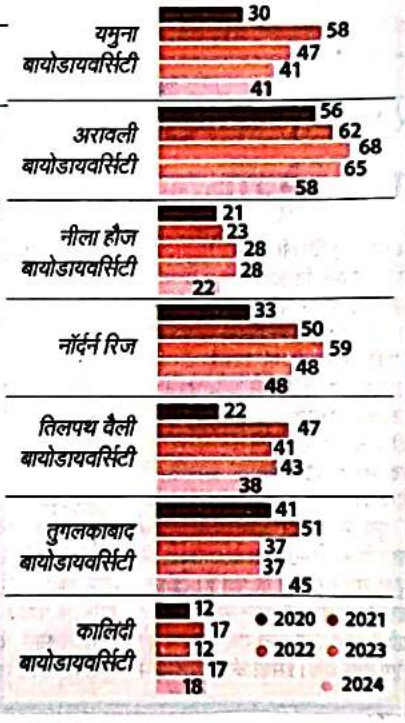

विश्लेषण में कई कॉलेज स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा

तितलियों से संबंधित यह आकलन समने आया है दिल्ली के सातों बायोडायवर्सिटी पार्क में हुए तितली विश्लेषण में। तितलियों की प्रजातियों और उनकी संख्या का पता लगाने के लिए यह विश्लेषण 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह के तहत किया गया। इसमें डीडीए के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, तिलपथ घाटी बायोडायवर्सिटी पार्क, उत्तरी रिज, नीला हौज, तुगलकाबाद बायोडायवर्सिटी पार्क और कालिंदी बायोडायवर्सिटी पार्क शामिल है। इस विश्लेषण में रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज, केशव महाविद्यालय, डीयू के केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली कौशल और उद्यमिता यूनिवर्सिटी, रामानुजम कॉलेज और अन्य सहित विभिन्न कॉलेज के स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने हिस्सा लिया। रोज सुबह 9.30 से 11.30 बजे तक 5 से 10 पर्यवेक्षकों की टीम तितलियों के व्यवहार को देखने निकलती थी। इस सर्वेक्षण का समन्वय बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम के सीनियर साइंटिस्टों, डॉ.आयश सुल्तान और मोहम्मद फैजल ने किया। एक हफ्ते में इन पार्कों में तितलियों की 68 प्रजातियां देखी गईं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2024 दैनिक जागरण TED----------

ब्लैक में बेचे जा रहे पीएम आवास योजना के फ्लैट : आप

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में झुग्गी वासियों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। आप ने कहा कि इसी शृंखला में अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कालकाजी में ऐसे ही फ्लैटों का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने कुछ झुग्गीवासियों को आबंटनपत्र भी दिए थे। आप ने आरोप लगाया कि एक स्टिंग आपरेशन में बात साफ हो रही है कि जिन फ्लैटों का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झुग्गी में रहने वाले लोगों को आवंटित करने के लिए किया था, उन फ्लैटों को एक बड़े भ्रष्टाचार के तहत ब्लैक में उन लोगों को बेचा जा रहा है, जो लोग झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग नहीं हैं। आप नेता व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी जांच की मांग की है। वहीं, एलजी सचिवालय ने कहा कि भारद्वाज द्वारा दिए गए बयान और आरोप स्पष्ट रूप से झूठे, बिना किसी आधार के और तथ्यों से रहित हैं। कहा है कि कालकाजी स्लम पुनर्वास परियोजना में एक भी फ्लैट/आवास इकाई किसी अयोग्य लाभार्थी को आवंटित नहीं की गई है और डीडीए के पास यह सुनिश्चित करने के लिए फुलप्रूफ प्रौद्योगिकी सक्षम सिस्टम हैं कि कोई फर्जी आवंटन/बिक्री न हो।

कितने गरीबों को दिल्ली सरकार ने दिए आवास : सचदेवा

वि. नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री केंद्रीय एजेंसियों के विरुद्ध भ्रम फैलाने, बढ़ाने का काम करते हैं। डीडीए के विरुद्ध भी आवास आवंटन को लेकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के भ्रामक आरोप लगाने की जगह मंत्री को बताना चाहिए कि पूर्व की शीला दीक्षित सरकार द्वारा राजीव आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए नरेला एवं बवाना में बनाए गए 40 हजार फ्लैट का आवंटन अब तक क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का काम गरीबों को घर उपलब्ध कराना है। दिल्ली सरकार बताएं कि पिछले 10 वर्षों में कितने गरीबों को घर दिए गए? दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं करने का भी कारण बताना चाहिए।

वीरेंद्र सचदेवा

झूठ बोल रही आप : डीडीए

फ्लैटों को ब्लैक किए जाने के आप के आरोप पर डीडीए ने कहा कि सौरभ भारद्वाज द्वारा दिए गए बयान और आरोप स्पष्ट रूप से झूठे, बिना किसी आधार के और तथ्यों से रहित है। कहा कि कालकाजी स्लम पुनर्वास परियोजना में एक भी फ्लैट या आवास किसी भी अयोग्य लाभार्थी को आवंटित नहीं किया गया है। डीडीए ने कहा कि कथित स्टिंग आपरेशन में दर्ज एक भी व्यक्ति उनसे दूर-दूर तक जुड़ा नहीं है। कथित फर्जी स्टिंग आपरेशन में दिखाए गए व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही एक पुलिस शिकायत दर्ज की जा चुकी है और वे लोग इस मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएंगे।

मौसम के बदले मिजाज के बावजूद राजधानी में तितलियों की संख्या स्थिर

जागरण संवाददाता,बाहरी दिल्ली : मानसून के बाद असामान्य गर्मी के बावजूद राजधानी में तितलियों की संख्या लगभग स्थिर पाई गई है। तितलियों को लेकर किए गए हालिया सर्वे में सामने आया कि देश के सभी पांच तितली परिवारों से तितलियों की 68 प्रजातियों की 8337 तितलियां दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के सभी सात बायो डायवर्सिटी पार्कों में मौजूद हैं। अरावली बायो डायवर्सिटी पार्क में सबसे ज्यादा तितली की 58 प्रजातियां पाई गईं। कालिंदी बायो डायवर्सिटी पार्क में सबसे कम 18 प्रजातियां मिलीं। विज्ञानियों का मानना है कि तितलियों की संख्या में स्थिरता जलवायु अनुकूलन का संकेत है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि बायो डायवर्सिटी पार्क तितलियों के आवास के तौर पर विकसित हो गए हैं।

- सबसे ज्यादा प्रजातियां अरावली बायो डायवर्सिटी पार्क में पाई गईं, सबसे कम कालिंदी पार्क में दिखीं
- सातों पार्कों में विभिन्न कालेजों के विद्यार्थियों ने की तितलियों की गणना

बायो डायवर्सिटी पार्क में पीपे पर बैठी तितली • सौ. बायो डायवर्सिटी पार्क

पिछले साल के आंकड़ों का अध्ययन करें तो तुगलकाबाद व कालिंदी बायो डायवर्सिटी पार्क में तितली प्रजाति की संख्या घटी है तो अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, नीला होज व तिलपथ वैली बायो डायवर्सिटी पार्क में तितलियों की प्रजाति की संख्या में कमी आई है। यमुना बायो डायवर्सिटी पार्क व नार्दर्न रिज प्रजातियों की संख्या स्थिर रही। बायो डायवर्सिटी पार्कों में प्लेन टाइगर, कामन इमिग्रेंट येलो आरेंज टिप, लेमन पैंसी, कामन गल और कामन ग्रास येलो प्रजाति की तितलियां देखी गईं।

डीडीए बायो डायवर्सिटी पार्क के प्रभारी विज्ञानी डा. फैयाज खुदसर के अनुसार पांच वर्षों के मौसम के बदलते मिजाज के बाद पार्क में तितली विविधता स्थिर बनी हुई है। इससे पता चलता है कि जैव विविधता से समृद्ध आवास जलवायु परिवर्तन अनुकूलन करने की क्षमता रखता है। डीडीए जैव विविधता पार्क जलवायु परिवर्तन के प्रभावों सहित पर्यावरणीय मुद्दों के अध्ययन के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। पिछले वर्ष के साथ अक्टूबर 2024 के मौसम के आंकड़ों की तुलना करने से पता चलता है कि इस वर्ष तापमान अधिक था, जिससे तितली देखने में थोड़ी गिरावट आई। मानसून के बाद असामान्य गर्मी के बावजूद, तितलियों की संख्या, विविधता और गतिविधि स्थिर रही।

यमुना जैव विविधता पार्क में घास के मैदान स्किपर तितलियों के लिए आदर्श हैं, जबकि अरावली जैव विविधता पार्क में पुनर्स्थापित जंगल और खुले आवास उपलब्ध कराता है। नार्दर्न रिज बायोडायवर्सिटी पार्क भी तितली प्रजातियों के लिए एक अनुकूल आवास के रूप में उभर रहा है। डीडीए के सात पार्कों में मनाए गए वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के दौरान रामजस कालेज, हिंदू कालेज, किरोड़ीमल कालेज, सत्यवती कालेज, इंद्रप्रस्थ महिला कालेज, केशव महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, रामानुजन कालेज सहित कई कालेजों के छात्र और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अलग-अलग समूहों में तितलियों की गणना और दस्तावेजीकरण किया गया। पर्यवेक्षकों ने वयस्क तितलियों को धूप सेंकते, प्रजनन करते, अंडे देते हुए रिकार्ड किया और मेजबान पौधों पर लार्वा और अंडे देखे। वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. आवशा सुल्ताना और मोहम्मद फैसल को देखरेख में सर्वे किया गया।

बायो डायवर्सिटी पार्कों में तितलियों की प्रजाति संख्या

पार्क	वर्ष 2020	2021	2022	2023	2024
यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क	30	58	47	41	41
अरावली पार्क	56	62	68	65	58
नीला होज पार्क	21	23	28	28	22
नार्दर्न रिज	33	50	59	48	48
तिलपथ वैली पार्क	22	47	41	43	38
तुगलकाबाद पार्क	41	51	37	37	45
कालिंदी पार्क	12	17	12	17	18

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- दैनिक जागरण www.Jagran.com नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2024 ----DATED----------

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी. सं.–09/2024/पीबी–I

डीडीए में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप-निदेशक (मिनिस्ट्रियल) (7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल–11) के 04 पदों को भरने के संबंध में आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तार।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दिविप्रा) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप–निदेशक (मिनिस्ट्रियल) (7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर–11) के 04 पदों को भरने के लिए रिक्ति सूचना वी.सं.–09/2024/पीबी–I दिनांक 12.08.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केंद्र/राज्य सरकार के अधीन भूमि और निर्मित संपत्तियों का आबंटन, संपत्तियों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने, मानव संसाधन विकास, भूमि प्रबंधन, राजस्व, सतर्कता, लैंड पूलिंग, अनधिकृत कॉलोनियों में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने इत्यादि से संबंधित कार्यदायित्व संभाल रहे पात्र अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए थे तथा परिपूर्ण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.09.2024 थी। यह तिथि अब 21.10.2024 तक आगे बढ़ा दी गई है।

आयुक्त (कार्मिक)

ddaofficial official_dda official_dda_ पर हमें फॉलो करें
"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखिए या 1800110332 टोल फ्री नं. डायल करें"

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सूचना

डीडीए के विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर परामर्शदाता के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डीडीए के विभिन्न विभागों में परामर्शदाता के रूप में 05 नायब तहसीलदार और 03 कानूनगो को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। यह नियुक्ति शुरुआत में 01 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे डीडीए की आवश्यकता और अभ्यर्थी के कार्य निष्पादन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	अनुभव	सेवानिवृत्ति के समय न्यूनतम ग्रेड वेतन
1.	नायब तहसीलदार	05	डीडीए भूमि के राजस्व कार्य में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव	पीबी–2 + जीपी 4200/– रुपये (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6)
2.	कानूनगो	03	डीडीए भूमि के राजस्व कार्य में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव	पीबी–1 + जीपी 2400/– रुपये (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4)

अनिवार्य योग्यता, अधिकतम आयु और अनुभव आदि से संबंधित पूर्ण अधिसूचना के साथ, आवेदन का निर्धारित प्रारूप डीडीए की वेबसाइट https://dda.gov.in/latest-jobs पर उपलब्ध है।

अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में अपने हस्ताक्षरित आवेदन की स्कैन की हुई पीडीएफ/जेपीईजी कॉपी ई–मेल के माध्यम से **ddpb4@dda.org.in** पर **25.10.2024 को शाम 05:00 बजे** तक भेजनी होगी।

डाक या फोन द्वारा किसी अन्य पत्राचार या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसका विवरण डीडीए वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

रिक्तियों की संख्या डीडीए की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

आयुक्त (कार्मिक)

हमें फॉलो करें @ddaofficial official_dda official_dda_
"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या 1800110332 डायल करें"